कानपुर, शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 49, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी...>Pg12

39 करोड़ रूपए की नोटिस 'लापता'...>Pg03

मूल्यः 2 ₹

एआई समिट में घुसकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

..तो क्या देश की प्रतिष्ठा पर 'हमला'

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय स्तर के एआई समिट के दौरान राजधानी के प्रमुख सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम में सुरक्षा घेरा टूटने और विरोध प्रदर्शन की घटना ने देश की वैश्विक छवि और सुरक्षा प्रबंधन पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्यक्रम के बीच भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से अंदर घुसकर नारेबाजी किए जाने से कुछ समय के लिए आयोजन बाधित हुआ और अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर केंद्रित इस हाई-प्रोफाइल समिट में कई देशों के प्रतिनिधि, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और निवेशक मौजूद थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारी समूह बैनर-पोस्टर लेकर प्रतिबंधित जोन तक पहुंच गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। अंतरराष्ट्रीय मंच पर हुए इस घटनाक्रम को प्रोटोकॉल और प्रतिष्ठा दोनों दृष्टि से गंभीर माना जा रहा है।

सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर परिसर खाली कराया। इसके बाद प्रवेश द्वारों पर जांच और कड़ी कर दी गई। सुरक्षा एजेंसियां अब एंट्री पास जारी करने की प्रक्रिया, सत्यापन प्रणाली और तैनात सुरक्षा परतों की विस्तृत समीक्षा कर रही हैं।

⇨ हाई-सिक्योरिटी स्थल में नारेबाजी से मचा हड़कंप, विदेशी प्रतिनिधियों के सामने हुआ हंगामा

घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वैश्विक निवेश और तकनीकी सहयोग से जुड़े मंच पर इस तरह का व्यवधान देश की साख को नुकसान पहुंचाता है। पार्टी ने इसे गैर-जिम्मेदाराना कृत्य बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तिलक मार्ग थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षा तैनाती का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।

क्या हुआ भारत मंडपम के अंदर?

- एआई समिट के दौरान अचानक विरोध प्रदर्शन
- बैनर-पोस्टर लेकर अंदरूनी जोन तक पहुंचे प्रदर्शनकारी
- टी शर्ट उतार कर लहराते दिखे कांग्रेस कार्यकर्ता
- पीएम के खिलाफ नारेबाजी, सत्र कुछ देर प्रभावित

क्यों गंभीर मानी जा रही घटना?

- अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हंगामा
- हाई-सिक्योरिटी स्थल में सुरक्षा घेरा टूटा
- वैश्विक मंच पर आयोजन क्षमता पर सवाल

अब क्या कार्रवाई हो रही

- सभी प्रदर्शनकारी हिरासत में
- सीसीटीवी फुटेज और एंट्री लॉग की जांच
- पास जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा
- संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी

खबरः एक नजर में

- एआई अंतरराष्ट्रीय समिट के दौरान भारत मंडपम में हंगामा
- यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सुरक्षा घेरा तोड़ने का आरोप
- वैश्विक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में नारेबाजी
- हाई-सिक्योरिटी जोन में प्रवेश व्यवस्था पर गंभीर सवाल
- सभी प्रदर्शनकारी हिरासत में, थाने में पूछताछ जारी
- पास वेरिफिकेशन और सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच शुरू
- घटना पर सियासी बयानबाज़ी तेज
- देश की प्रतिष्ठा और आयोजन क्षमता पर उठे प्रश्न

अधिकारियों के द्वारा कानपुर में समय नहीं दिए जाने के कारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कई योजनाएं ठप

यूपीसीडा की कार्यप्रणाली पर सीएजी की कड़ी टिप्पणी!

मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सीईओ मयूर माहेश्वरी की विदाई होने के बाद भी फिलहाल हालात सुधारते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में तैनात सीईओ विजय किरण आनंद की अन्य विभागों में व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पा रहे हैं इसके चलते प्राधिकरण की तमाम योजनाएं में फेल हो रही है.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की प्रतिवेदन संख्या 14/2025 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2021-22 (मार्च 2024 तक अद्यतन) के दौरान भूमि अधिग्रहण, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, भूखंड आवंटन तथा आंतरिक नियंत्रण–चारों प्रमुख क्षेत्रों में बड़ी खामियां पाई गईं।

⇨ भूमि अधिग्रहण से लेकर नियंत्रण तक गंभीर खामियां उजागर

आंतरिक नियंत्रण भी कमजोर

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्राधिकरण के भीतर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभाव रहा, जिससे वित्तीय अनुशासन और परियोजनाओं की निगरानी प्रभावित हुई। सीएजी ने सिफारिश की है कि यूपीसीडा स्पष्ट विकास योजनाएं बनाए, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध करे तथा वित्तीय प्रबंधन और नियंत्रण तंत्र को मजबूत करे, ताकि औद्योगिक विकास को संतुलित और प्रभावी दिशा मिल सके।

सीएजी ने स्पष्ट किया कि कई मामलों में सरकारी मंजूरी के बिना ही विनियम बनाए गए, जबकि परिप्रेक्ष्य एवं विकास योजनाओं का अभाव रहा। बोली और ठेका प्रक्रिया में भी लापरवाही सामने आई, वहीं लेखा-प्रबंधन की कमजोरियों के कारण औद्योगिक विकास असंतुलित और अनियोजित स्थिति में पहुंच गया।

कागजों में सिमटा औद्योगिक विकास

- रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 154 औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 49,395 एकड़ है। लेकिन इन क्षेत्रों के नियोजित विकास की दिशा में ठोस प्रगति नहीं हो सकी।
- ऑडिट अवधि के दौरान भूमि अधिग्रहण की स्थिति बेहद कमजोर पाई गई।
- छह वर्षों में केवल एक वर्ष (2020-21) में ही लक्ष्य हासिल हुआ।
- शेष वर्षों में लक्ष्य से कमी 27.6 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक रही।
- दो वर्षों में तो कोई भी भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया।

बोर्ड परीक्षा में उलझे परिषदीय स्कूलों के शिक्षक !

शिक्षक नेताओं ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में शिक्षकों की ड्यूटी लगाना नियम विरुद्ध

» 50 फीसदी सरकारी योजनाओं का संचालन करते हैं परिषदीय स्कूलों के शिक्षक

» परिषदीय शिक्षकों को सरकार ने समझ लिया है ब्रह्मास्त्र, जो कार्य कोई नहीं कर पाता उसमें इन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। यह सवाल अब केवल व्यवस्था का नहीं प्राथमिक शिक्षा के सम्मान और प्राथमिकता का सवाल बन चुका है। देश में बोर्ड परीक्षाएँ केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं होतीं। सीबीएसई और आईसीएसई जैसे बोर्ड भी हर साल बड़े पैमाने पर परीक्षाएँ कराते हैं और वे अपने ही संस्थानों के स्टाफ, अपने संसाधनों और अपनी व्यवस्थाओं के सहारे यह कार्य अच्छे से पूरा करते हैं। उन्हें न तो प्राथमिक शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है और न ही अन्य विभागों के कर्मचारियों की स्थायी निर्भरता बनानी पड़ती है। ऐसे में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएँ माध्यमिक विद्यालयों के अपने शिक्षकों और स्टाफ के सहारे क्यों नहीं कराई जा सकतीं?

वास्तविक समस्या संसाधनों की कमी से अधिक सोच की कमी है। बेसिक शिक्षा के शिक्षक व्यवस्था की नजर में हमेशा एक उपलब्ध संसाधन की तरह देखे गए हैं जहाँ आवश्यकता हुई वहीं लगा दिया। कभी चुनाव, कभी जनगणना, कभी सर्वेक्षण, कभी पुनरीक्षण अभियान, कभी बीएलओ ड्यूटी और अब यू पी बोर्ड परीक्षाएँ। सवाल यह नहीं कि ये कार्य महत्वपूर्ण नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या प्राथमिक शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? क्या कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का नियमित शिक्षण इतना गौण है कि उसे बार-बार बाधित किया जा सके? विडंबना यह है कि एक ही समय में कई अभियानों का दबाव बना दिया जाता है। विशेष गहन पुनरीक्षण, पंचायत पुनरीक्षण, बीएलओ कार्य और अब बोर्ड परीक्षा ड्यूटी। परिणाम यह होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की उपलब्धता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। कागजों में स्कूल खुले रहते हैं पर कक्षाओं में शिक्षण का प्रवाह टूट जाता है। जिन बच्चों को बुनियादी भाषा और गणित की सबसे अधिक आवश्यकता है, वही सबसे अधिक उपेक्षित हो जाते हैं। यह भी सोचने का विषय है कि जब माध्यमिक स्तर पर सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों की बड़ी संख्या मौजूद है तो परीक्षा प्रबंधन के लिए उसी व्यवस्था को मजबूत क्यों नहीं किया जाता? परीक्षा केंद्र भले 20-30 प्रतिशत विद्यालय ही बनते हों लेकिन पर्यवेक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी उसी स्तर के शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच बाँटी जा सकती है। हर बार बेसिक शिक्षा को थोक के भाव झोंक देना प्रशासनिक सुविधा तो हो सकती है लेकिन यह शैक्षिक दृष्टि से दूरदर्शिता नहीं है। समस्या का एक गंभीर मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। जब बार-बार बेसिक शिक्षकों को हर अतिरिक्त कार्य के लिए सबसे पहले चुना जाता है तो यह संदेश जाता है कि उनका मूल कार्य शिक्षण व्यवस्था की प्राथमिकता नहीं है। यह स्थिति न केवल कार्य-संतोष को प्रभावित करती है बल्कि प्राथमिक शिक्षा की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी कमजोर करती है। अब समय आ गया है कि जिम्मेदार स्तर पर गंभीर चिंतन किया जाए। क्या प्रत्येक विभाग को अपने मूल कार्य के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया जाना चाहिए? क्या बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक स्वतंत्र, प्रशिक्षित और स्थायी प्रबंधन तंत्र विकसित नहीं किया जा सकता? क्या विभिन्न प्रशासनिक और निर्वाचन कार्यों की समय-सारिणी इस तरह नहीं बनाई जा सकती कि प्राथमिक शिक्षा प्रभावित न हो? शिक्षा व्यवस्था की सबसे मजबूत नींव प्राथमिक स्तर होता है। यदि यही स्तर बार-बार बाधित होगा तो ऊपर की पूरी संरचना कमजोर होती जाएगी। बोर्ड परीक्षा का सुचारु संचालन महत्वपूर्ण है लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कक्षा में बैठा वह छोटा बच्चा रोज अपने शिक्षक को उपलब्ध पाए। प्रशासनिक सुविधा और शैक्षिक प्राथमिकता के बीच संतुलन बनाना ही अब सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि व्यवस्था सचमुच शिक्षा सुधार को लेकर गंभीर है तो उसे यह तय करना होगा कि बेसिक शिक्षा उपलब्ध मानव संसाधन नहीं बल्कि भविष्य निर्माण का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब यह समझ नीति का हिस्सा बनेगी तभी प्राथमिक विद्यालयों में स्थिरता, सम्मान और गुणवत्ता का वातावरण बन सकेगा।

बंद कमरे में पंखे से लटका मिला छात्रा का शव

कानपुर। साढ़ थाना क्षेत्र के चिरली गांव में यूपीएसआई की तैयारी कर रही एक छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे आत्महत्या के कारणों पर सस्पेंस बना हुआ है।कानपुर में साढ़ थाना क्षेत्र के चिरली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रयागराज में रहकर दरोगा बनने का सपना संजोने वाली एक होनहार छात्रा ने गुरुवार को अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

बताया गया कि वह बीते मंगलवार को ही प्रयागराज से अपने गांव वापस लौटी थी। गुरुवार सुबह सेजल अपनी मां विमला, जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं, उन्हें केंद्र छोड़ने गई थी। वहां से लौटने के बाद उसने ऊपरी मंजिल के कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दोपहर में जब मां ड्यूटी खत्म कर घर लौटी, तो कमरे का नजारा देख उनकी चीख निकल गई।

केडीए: इल्डिगो टाउनशिप की 39 करोड़ रूपए की नोटिस 'लापता'

इल्डिगो टाउनशिप रियल स्टेट कंपनी ने जोन-2 जवाहरपुरम में केडीए की जमीन खरीदी थी

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण-केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्यालय ने प्राधिकरण की व्यवस्था और पारदर्शिता बढाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब प्राधिकरण में 5 बजे के बाद इंट्री पर रोक लगा दी गई है, इसका साफ मकसद है कि दलाल और बाहरी लोगों के दखल को खत्म किया जा सके। वहीं, केडीए में इल्डिगो टाउनशिप एंड हाउसिंग लिमिटेड कंपनी को जारी किया गया 39 करोड़ रूए वसूली का नोटिस लापता हो गया है। उसकी फाइल भी नहीं मिल रही है, बताया कि जा रहा है कि फाइल में हेराफेरी की गई है।

सूत्रों के अनुसार इल्डिगो टाउनशिप को प्राधिकरण के जोन-2 जवाहरपुरम सेक्टर 9 पुराना-14 में क्षेत्रफल 45310.00 वर्गमीटर दिनांक 30-04-2025 और 9, 950.71 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई थी। इसके लिए इल्डिगो टाउनशिप लिमिटेड को केडीए में 39 करोड़ 18 लाख रूए जमा करने थे।

⇨ अवशेष धनराशि 39 करोड़ और केडीए में जमा करने थे लेकिन फाइल गायब कर दी गई

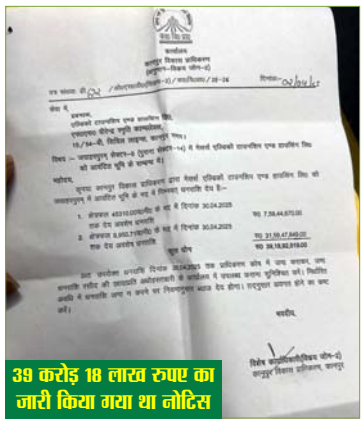

39 करोड़ 18 लाख रुपए का जारी किया गया था नोटिस

इस संबंध में तत्कालीन ओएसडी डा0 रविप्रताप सिंह की ओर से 2-04-2025 को नोटिस पत्र इल्डिगो टाउनशिप एफएफ वीरेंद्र स्मृति कांपलेक्स सिविल लांइस को जारी किया गया था, इसमें लिखा गया था कि 30 अप्रैल 2025 तक धनराशि प्राधिकरण में कोष में जमा कर दें अन्यथा ब्याज सहित राशि वसूल की जाएगी। सूत्रों का दावा है कि इसी बीच डा. रविप्रताप सिंह का तबादला अन्य जोन में हो गया। सेल विभाग में तैनात लिपिकों ने मिलीभगत करके उक्त नोटिस गायब कर दी।

अब केडीए में एक भी रूप्या नहीं जमा किया गया। अब यह नोटिस सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बडी धनराशि जमा करने में अधिकारियों ने कोई रूचि क्यों नहीं ली। बताया जा रहा है कि फाइल गायब है उसके कई पेज भी गायब हैं। वहीं, इस मामले में कर्मचारी नेताओं ने धांधली की आशंका जताई है।

प्रकरण संज्ञान में आया है कि इतनी बडी धनराशि क्यों नहीं जमा हुई, इस संबंध में लिपिक को भी तलब किया गया है। फाइल देखने के बाद ही स्थिति और स्पष्ट होगी, उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

मीनाक्षी गुप्ता, ओएसडी जोन-2 सेल

कानपुर-सागर हाईवे पर 30 किमी लंबा महाजाम, 12 घंटे से यातायात ठप

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर-सागर हाईवे पर बिधनू थाना क्षेत्र के रमईपुर चौराहे के पास भीषण जाम ने यातायात व्यवस्था की पोल खोल दी। पिछले करीब 12 घंटे से ट्रैफिक पूरी तरह रेंगता रहा और लगभग 30 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। जाम में हजारों यात्री, स्कूली वाहन और एंबुलेंस फंसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार देर रात दो ट्रकों के खराब होकर बीच सड़क पर खड़े हो जाने से आवागमन बाधित हुआ। शुरुआती स्तर पर ट्रैफिक को डायवर्ट करने और खराब वाहनों को तुरंत हटाने की प्रभावी व्यवस्था न होने से स्थिति बिगड़ती चली गई। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर ट्रकों को हटाया, लेकिन तब तक वाहनों का दबाव इतना बढ़ चुका था कि जाम खुल नहीं सका।

रात में सहालग के कारण भारी वाहन और निजी गाड़ियों की संख्या ज्यादा रही। कई डंपर और ट्रक आड़े-तिरछे खड़े रहे, कुछ चालक वाहनों में ही सो गए, जिससे रास्ता और संकरा हो गया। सुबह तक जाम रमईपुर चौराहे से पतारा चौकी क्षेत्र तक फैल गया। लंबी दूरी के यात्रियों को न खाने-पीने की सुविधा मिली और न ही शौचालय जैसी बुनियादी व्यवस्था, जिससे नाराजगी बढ़ती गई।

⇨ यातायात प्रबंधन पूरी तरह हुआ फेल, एंबुलेंस और स्कूली वाहन भी फंसे रहे

जाम में फंसे लोगों ने बताया कि ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल देर से पहुंचा और शुरुआती घंटों में कोई स्पष्ट रूट प्लान लागू नहीं किया गया। इसका सीधा असर स्कूली बच्चों और मरीजों पर पड़ा। कई स्कूली वाहन घंटों फंसे रहे, जबकि मरीजों को लेकर जा रही एंबुलेंस को वैकल्पिक कच्चे रास्तों का सहारा लेना पड़ा। पतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधीक्षक डॉ. अभिषेक कटियार ने बताया कि वह करीब डेढ़ घंटे तक जाम में फंसे रहे, जिससे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित हुआ। कई शिक्षक भी घंटों देरी से स्कूल पहुंचे।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार जाम की सूचना मिलते ही अतिरिक्त बल तैनात कर डायवर्जन लागू किया गया है और वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बेहतर यातायात प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया होती तो हालात इतने नहीं बिगड़ते।

ग्यारहवीं पुण्यतिथि

॥ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः ॥
॥ न चैनं क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः ॥

"शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकती, अग्नि इसे जला नही सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकती अर्थात प्रत्येक स्थिति में आत्मा अपरिवर्तनीय है।"

ब्रह्मलीन तपेश्वरी प्रसाद गुप्त
17 फरवरी 1947 | 20 फरवरी 2015

"स्मृति आपकी, अनुकरण हमारा, मार्गदर्शन आपका, प्रयत्न हमारा
दिशा आपकी, अनुसरण हमारा, संस्कृति आपकी, संकल्प हमारा"

स्मृति संवेदित
मयूर परिवार

MAYUR
HAPPINESS ALWAYS
~SINCE 1994~

एक्शन में डीएम: 11.26 हेक्टेयर नजूल जमीन के 11 भूखंडों पर प्रशासन ने लिया कब्जा

» मुख्य संवाददाता/स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। शहर के प्रमुख शहरी इलाकों में स्थित करीब 11.26 हेक्टेयर बहुमूल्य नजूल भूमि पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुनर्प्रवेश कर सरकारी कब्जा ले लिया है। यह भूमि पूर्व की औद्योगिक इकाई ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन (बीआईसी) की मिल परिसंपत्तियों से संबंधित बताई गई है और सिविल लाइंस, कूपरगंज तथा चुन्नीगंज क्षेत्र में फैले कुल 11 भूखंडों में स्थित है। प्रशासन के अनुसार इन भूखंडों का उपयोग अब सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

जिलाधिकारी के आदेश पर सिविल लाइंस, कूपरगंज व चुन्नीगंज में कार्रवाई

यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में की गई। संयुक्त मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर के निर्देशन में तहसीलदार सदर और राजस्व व नजूल विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर ब्लॉक संख्या 9, 11, 13 और 82 से 85 तक के चिन्हित भूखंडों पर कब्जा लिया। कार्रवाई के दौरान सभी 11 संपत्तियों पर सरकारी स्वामित्व दर्शाने वाले बोर्ड भी लगवा दिए गए हैं। बोर्ड पर स्पष्ट चेतावनी दर्ज है कि यह भूमि सरकारी संपत्ति है और किसी भी प्रकार का अतिक्रमण दंडनीय अपराध माना जाएगा।

राजस्व अधिकारियों ने बताया कि मौके पर कुछ स्थानों पर लोगों का कब्जा और उपयोग भी पाया गया है। ऐसे मामलों में विस्तृत सर्वे कराया जा रहा है।

सर्वे के बाद संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया विधिक प्रावधानों के तहत चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।

जांच में पाया गया कि इन 11 संपत्तियों की पट्टा अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। न तो किसी अधिकृत लिक्विडेटर की नियुक्ति थी, न फ्री-होल्ड कराने के लिए निर्धारित धनराशि जमा की गई थी और न ही पट्टा अवधि बढ़ाने के लिए नजूल अनुभाग में कोई वैध आवेदन उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त लीज रेंट भी जमा नहीं किया गया था। कई स्थानों पर पट्टा शर्तों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती भी मिलीं।

शासन के 16 जनवरी 2026 के निर्देशों के अनुपालन में इन सभी भूखंडों को पुनर्प्रवेश के बाद अनावंटित सरकारी भूमि के रूप में दर्ज कर लिया गया है। संबंधित अभिलेखों में प्रविष्टि की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

प्रशासन का कहना है कि नजूल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार शाश्वत पट्टा मान्य नहीं है और निर्धारित अवधि से अधिक नवीनीकरण का प्रावधान भी नहीं है, इसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

गोकुलधाम योजना : उन्नाव के 163 फ्लैटों का लॉटरी से आवंटन

कानपुर विकास प्राधिकरण की लाटरी में 163 आवेदकों को मिला फ्लैट

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मगरवारा, उन्नाव स्थित गोकुलधाम योजना के फ्लैटों की लाटरी प्रक्रिया सम्पन्न कराई गई। लाटरी में कुल 163 आवेदक फ्लैट पाने में सफल रहे, जबकि 25 आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है।

प्राधिकरण अधिकारियों के निर्देशन में आयोजित इस लाटरी में निजी विकासकर्ता मेसर्स ट्रेड स्टोन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए अवशेष 218 फ्लैटों के सापेक्ष आवंटन किया गया।

अधिकारियों के अनुसार पहले से आवंटित फ्लैटों में यदि कोई आवंटी निरस्तीकरण या धनवापसी कराता है तो प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को आरक्षण नियमों के अनुसार आवंटन दिया जाएगा।बताया गया कि इन फ्लैटों के लिए 04.02.2025 से 05.03.2025 तक निर्धारित बैंकों के माध्यम से पंजीकरण फार्म जमा कराए गए थे। कुल 242 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से जांच के बाद 221 पात्र आवेदकों की सूची सूचना पट और वेबसाइट पर प्रकाशित कर आपत्तियां मांगी गईं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद लाटरी कार्यक्रम प्राधिकरण भवन स्थित अटल बिहारी बाजपेयी प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया।कार्यक्रम में उन्नाव प्रशासन के नामित अधिकारी, परियोजना अधिकारी, प्राधिकरण स्टाफ, सुरक्षा बल और स्वरूप नगर थाना पुलिस की मौजूदगी रही। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थल पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के साथ सीधा प्रसारण भी किया गया।

लाटरी में अपना नाम आने पर कई आवेदकों ने खुशी व्यक्त करते हुए प्राधिकरण का आभार जताया और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बताया।

केडीए में देर शाम तक लॉटरी प्रक्रिया को सिस्टम में अपडेट किया गया

आज 564 प्लॉटों की ऑनलाइन लॉटरी लगेगी

कानपुर.।कानपुर विकास प्राधिकरण में आज 564 प्लाटों की लॉटरी लगाई जाएगी. इसके लिए 26 सौ आवेदन आए हैं. विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) मीनाक्षी गुप्ता ने बताया कि शताब्दी नगर और जवाहरपुरम के प्लाटों की आज ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है.

सफाई व्यवस्था देखने निकले नगर आयुक्त को मिली कई जगह -जगह गंदगी

» सिटी की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सख्ती, लापरवाही पर वेतन रोकने के निर्देश

» रमजान और होली को लेकर विशेष निर्देश दिए गए

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। नगर निगम के नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रॉयल क्लिफ चौराहा, पोस्टमार्टम हाउस, हैलट, गोल चौराहा, रावतपुर क्रासिंग, गीता नगर, गुरुदेव चौराहा, अवधपुरी चौराहा तथा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय चौराहे के आसपास सफाई व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया।

निरीक्षण में कई स्थानों पर सड़कों पर गंदगी मिलने पर नगर आयुक्त ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।

रॉयल क्लिफ चौराहे से रावतपुर गोल चौराहे तक झाड़ू न लगने और कचरा फैले होने पर जोनल स्वच्छता अधिकारी को दोपहर 12.00 बजे तक हर हाल में सफाई कर जियोटैग फोटो प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

लापरवाही पर कार्रवाई

रावतपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे और सब्जी बाजार क्षेत्र में गंदगी पाए जाने पर सफाई व्यवस्था में शिथिलता मानते हुए सफाई निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

साथ ही कई सफाई नायकों और कर्मचारियों का एक-एक दिन का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

नगर आयुक्त ने कहा कि आवारा पशुओं पर भी सख्ती करें

गुरुदेव चौराहे के सामने आवारा पशु घूमते मिलने पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को तत्काल अभियान चलाकर पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजने के निर्देश दिए गए।

नगर आयुक्त ने सभी जोन अधिकारियों को रोजाना क्षेत्र भ्रमण कर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

रमजान माह को देखते हुए सभी मस्जिदों और उनके आसपास विशेष सफाई रखने तथा मुस्लिम संगठनों से समन्वय बनाए रखने को कहा गया।

साथ ही होलिका दहन स्थलों पर सड़क की सुरक्षा के लिए पहले मिट्टी बिछाने के बाद ही लकड़ी रखने

और कार्यक्रम कराने के निर्देश मुख्य अभियंता को दिए गए।

निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय क्षेत्र में सफाई व्यवस्था

संतोषजनक पाई गई। नगर निगम ने संकेत दिया है कि आगे भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे।

सम्पादकीय

एपस्टीन प्रकरण—सत्ता, प्रभाव और पारदर्शिता की कसौटी

डॉ. मजहर नकवी
(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार व विदेशी मामलों के एक्सपर्ट हैं)

यौन शोषण और सत्ता-संबंधों से जुड़े मामलों में सच का सामने आना अक्सर सबसे कठिन प्रक्रिया होती है। अमेरिकी कारोबारी और दोषसिद्ध यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ा मामला इसी जटिलता का प्रतीक बन चुका है। यह केवल एक आपराधिक प्रकरण नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभाव, संस्थागत पारदर्शिता और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता की भी परीक्षा है।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर एपस्टीन से पुराने संबंधों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। चुनावी दौर में एपस्टीन फाइलों से जुड़े नाम सार्वजनिक करने के वादे और बाद में बदलते रुख ने बहस को और तेज किया है।

दूसरी ओर, अमेरिकी संसद और जांच एजेंसियों पर भी लगातार दबाव रहा है कि वे इस मामले में पूरी सच्चाई सामने लाएँ। पीड़ित महिलाओं और मानवाधिकार समूहों का तर्क है कि न्याय तभी संभव है जब प्रभावशाली नामों को भी जांच के दायरे में समान रूप से रखा जाए।एपस्टीन प्रकरण ने दुनिया को चौंकाया क्योंकि इसमें कथित तौर पर कई देशों के प्रभावशाली लोग, कारोबारी और राजनेता उसके संपर्क दायरे में बताए गए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सहित कई चर्चित हस्तियों के नाम सार्वजनिक विमर्श में आए, हालांकि कानूनी दोष सिद्धि और आरोप—इन दोनों के बीच का फर्क समझना भी उतना ही जरूरी है। मीडिया ट्रायल और न्यायिक प्रक्रिया में संतुलन लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल शर्त है। जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन की भूमिका, दस्तावेजों के आंशिक सार्वजनिक होने और संपादित फाइलों पर भी सवाल उठे हैं। आलोचकों का कहना है कि अगर दस्तावेजों में अत्यधिक संपादन होगा तो पारदर्शिता का उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाएगा। न्याय व्यवस्था का भरोसा तथ्यों की स्पष्टता से बनता है, न कि आधी-अधूरी जानकारी से।एपस्टीन की सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल को सजा मिल चुकी है, लेकिन पीड़ितों का एक वर्ग अब भी मानता है कि पूरा नेटवर्क बेनकाब नहीं हुआ। उनका सवाल सीधा है यदि अपराध संगठित और व्यापक था, तो जिम्मेदारी भी व्यापक स्तर पर तय होनी चाहिए।यह मामला अब डेमोक्रेट बनाम रिपब्लिकन या पक्ष बनाम विपक्ष की बहस से आगे बढ़ चुका है। असली मुद्दा है पीड़ितों को न्याय, प्रभावशाली लोगों की जवाबदेही और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता। लोकतंत्र में संस्थाओं की ताकत इसी से मापी जाती है कि वे शक्तिशाली लोगों की भी निष्पक्ष जांच कर सकें।

बंगाल का भविष्य: धर्म की लहर या प्रगति की राह

बलवंत सचदेवा

बंगाल की राजनीति लंबे समय तक वर्ग-संघर्ष, वाम वैचारिकी और सामाजिक न्याय के नारों के इर्द-गिर्द घूमती रही। लगभग तीन दशक तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में वाम मोर्चा सत्ता में रहा। उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व था। किंतु 2011 में सत्ता परिवर्तन के साथ एक नई धुरी बनी-तृणमूल बनाम भाजपा।पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले अभी बाकी हो, पर राजनीतिक रणभेरी बज चुकी है। इस बार संकेत साफ हैं-चुनाव विकास बनाम विकास के दावे पर नहीं, बल्कि पहचान, अस्मिता और धर्म की ध्वजा के इर्द-गिर्द घूम सकता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य भर में प्रस्तावित हिंदू सम्मेलनों को भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक उत्सव भर नहीं, बल्कि चुनावी अवसर में बदलने की रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी यह समझ लिया है कि यदि चुनाव की जमीन धार्मिक विमर्श पर खिसकती है तो उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोलकाता के न्यू टाउन में 'दुर्गा आंगन' का शिलान्यास और उसे बंगाली अस्मिता से जोड़ने का प्रयास इसी रणनीतिक सजगता का हिस्सा है।बंगाल की राजनीति लंबे समय तक वर्ग-संघर्ष, वाम वैचारिकी और सामाजिक न्याय के नारों के इर्द-गिर्द घूमती रही। लगभग तीन दशक तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में वाम मोर्चा सत्ता में रहा। उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व था। किंतु 2011 में सत्ता परिवर्तन के साथ एक नई धुरी बनी-तृणमूल बनाम भाजपा। आज स्थिति यह है कि वाम और कांग्रेस हाशिए पर हैं और मुकाबला दो ध्रुवों के बीच सिमट चुका है। यही द्विध्रुवीयता चुनाव को अधिक तीखा और अधिक पहचान-केन्द्रित बना रही है। भाजपा का अभियान चार प्रमुख सूत्रों पर टिका है-बंगाल में हिंदू खतरे में है, बांग्लादेशी घुसपैठ, महिलाओं की असुरक्षा और भ्रष्टाचार। सीमावर्ती जिलों का उदाहरण देकर यह संदेश गढ़ा जा रहा है कि जनसांख्यिकीय संतुलन बदल रहा है। अवैध घुसपैठ का प्रश्न नया नहीं है, पर उसे इस समय राजनीतिक ऊर्जा के साथ जोड़ा जा रहा है। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की घटना, शिक्षक भर्ती घोटाले, हिन्दुओं पर बढ़ते अत्याचार एवं भ्रष्टाचार जैसे प्रसंगों को शासन की विफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

भाजपा का लक्ष्य स्पष्ट है-70 प्रतिशत हिंदू मतदाताओं में एक साझा असुरक्षा-बोध निर्मित करना, हिन्दुओं को जागृत करना और उसे मतदान व्यवहार में रूपांतरित करना। आज बंगाल में विकास की सबसे बड़ी बाधा घुसपैठियों का बढ़ना है। घुसपैठियों पर विराम लगाना चाहिए न कि इस मुद्दे पर राजनीति हो।ममता बनर्जी की चुनौती दोहरी है। एक ओर उन्हें यह संदेश देना है कि वे अल्पसंख्यकों की संरक्षक हैं, दूसरी ओर हिंदू मतदाताओं को यह विश्वास भी दिलाना है कि उनकी आस्था और अस्मिता सुरक्षित है। 2021 के चुनाव में जब भाजपा ने 'जय श्रीराम' के नारे को आक्रामक रूप से उछाला, तब ममता ने 'जय मां दुर्गा' और 'चंडी पाठ' के माध्यम से एक सांस्कृतिक प्रत्युत्तर दिया था। इस बार वे दुर्गा आंगन जैसे प्रतीकों के जरिए यह संकेत दे रही हैं कि बंगाली हिंदू पहचान भाजपा की बपौती नहीं है। वे धर्म को राष्ट्रवाद की बजाय क्षेत्रीय अस्मिता के साथ जोड़ती हैं-बंगाल अपनी संस्कृति से हिंदू है, पर उसकी राजनीति बहुलतावादी है-यह उनका अंतर्निहित संदेश है। इसी बीच मुर्शिदाबाद में पूर्व तृणमूल नेता हुमायूं कबीर द्वारा 'बाबरी मस्जिद' के शिलान्यास की पहल ने नई जटिलता जोड़ दी है। इससे मुस्लिम मतदाताओं के भीतर एक अलग ध्रुवीकरण की संभावना पैदा हुई है। यदि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है, तो तृणमूल का गणित प्रभावित हो सकती है। 2021 में उसे लगभग 48 प्रतिशत वोट और 223 सीटें मिली थीं- मुस्लिम मतों का एकमुश्त समर्थन निर्णायक था।

खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी मौसम अनुकूल खेती

फसलों पर असर

निरंजन शर्मा

जलवायु बदलाव के चलते फरवरी में तापमान सामान्य से ज्यादा हो रहा है। इसका प्रभाव गेहूं आदि रबी फसलों व आम की पैदावार पर है। यानी खाद्य सुरक्षा संकट में है। इसका समाधान 'क्लाइमेट स्मार्ट कृषि' में निहित है। यानी इसमें मल्चिंग, माइक्रो सिंचाई व 'हीट टॉलरेंट' किस्में मददगार होंगी।फरवरी का महीना आमतौर पर गुलाबी ठंड और वसंत की मंद बयार का प्रतीक माना जाता रहा है। यह वह समय होता है जब रबी की फसलें और आम के बगीचे अपने यौवन पर होते हैं। लेकिन साल 2026 की यह फरवरी डराने वाली है। फरवरी के मध्य में ही देश के एक बड़े हिस्से में पारा 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है, जो सामान्य से करीब 5 से 7 डिग्री अधिक है। यह केवल एक मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं है, बल्कि 'ग्लोबल वार्मिंग' का वह क्रूर चेहरा है जो सीधे हमारी थाली और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रहार कर रहा है।

जलवायु परिवर्तन का सबसे घातक प्रहार हमारी खाद्य सुरक्षा और 'फलों के राजा' आम पर हो रहा है। रबी की मुख्य फसल गेहूं के लिए फरवरी का दूसरा पखवाड़ा 'ग्रैन फिलिंग' यानी बालियों में दाना भरने की अवस्था का होता है। इस नाजुक दौर में अचानक बढ़ी गर्मी थर्मल स्ट्रेस पैदा कर रही है। जब तापमान 30 डिग्री के ऊपर बना रहता है, तो पौधों के भीतर चयापचय की प्रक्रिया असामान्य रूप से तेज हो जाती है और दाना पूरी तरह विकसित होने से पहले ही सख्त होने लगता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में फोर्स्ड मेच्योरिटी कहा जाता है। परिणामस्वरूप, दाना छोटा, हल्का और झुर्रियों वाला रह जाता है। कृषि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि तापमान में इसी तरह की वृद्धि जारी रही, तो गेहूं की पैदावार में प्रति

हेक्टेयर 15 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। सागर और औरैया के खेतों से आ रही रिपोर्टें बताती हैं कि गेहूं की बालियां समय से पहले सफेद पड़ रही हैं, जो सीधे तौर पर किसान की साल भर की मेहनत पर पानी फेरने जैसा है।विशेषज्ञ बताते हैं कि आम का पुष्पन जाड़े के अंत और वसंत की शुरुआत में स्थिर तापमान और मध्यम आर्द्रता में होता रहा है। किंतु तापमान की वर्तमान अनिश्चितता ने इस प्रक्रिया को 'रोलर-कोस्टर' बना दिया है। इसके विपरीत, यदि अचानक तापमान गिरता है, तो फूलों का खुलना असमान हो जाता है। सुबह की अत्यधिक नमी फफूंदजनित रोगों का जोखिम बढ़ा रही है, जबकि दोपहर की शुष्क हवा पराग के अंकुरण को बाधित कर रही है। नतीजा यह है कि या तो फूल गिर रहे हैं, या निषेचन के बाद भी फल टिक नहीं पा रहे हैं।आमतौर पर सर्दियों में होने वाली 'मावट' या बारिश फसलों के लिए अमृत समान होती थी, लेकिन इस साल शुष्कता और बढ़ती गर्मी ने मिट्टी की नमी को सोख लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले एक दशक में फरवरी के महीने में लू जैसी स्थितियों की आवृत्ति बढ़ी है। इस पैटर्न में भारत के मौसम चक्र से 'वसंत' ऋतु धीरे-धीरे गायब हो रही है। इसका असर केवल गेहूं और आम पर ही नहीं, बल्कि सरसों और दलहन पर भी पड़ रहा है। सरसों की फलियों में तेल की मात्रा कम होने की आशंका है और चने के पौधों में फूल समय से पहले ही झड़ रहे हैं।इस विकट परिस्थिति का निदान अब केवल पारंपरिक खेती के ढर्रे पर चलकर संभव नहीं है। हमें 'क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर' यानी जलवायु-अनुकूल कृषि की ओर युद्धस्तर पर बढ़ना होगा। मिट्टी की नमी बचाने के लिए गन्ने की सूखी पत्तियों, भूसे या सूखी घास से 'मल्चिंग' करना अब अनिवार्यता है। यह तकनीक सतह के तापमान को स्थिर रखती है और पानी के वाष्पीकरण को रोकती है। इसके साथ ही, सूक्ष्म-सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) को अपनाकर 'कम पानी—ज़्यादा असर' के सिद्धांत पर काम करना होगा। बागों की मेढ़ों पर कटहल, बांस या नीम जैसे वायुरोधी अवरोध लगाने चाहिए ताकि तेज पछिया हवाओं से फूलों और फलों का बचाव हो सके।वैज्ञानिकों के अनुसार, पुष्पन के दौरान बोरॉन और जिंक जैसे सूक्ष्म-पोषक तत्वों का संतुलित छिड़काव फूलों की जीवन-क्षमता को बढ़ा सकता है।

स्कूल में 'दिल का त्रिकोण' बना टकराव, छात्रा को लेकर दो छात्र भिड़े

पहले पुलिस को दी तहरीर, फिर पीछे हटे संचालक, नाबालिग शामिल होने से मामला दबा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। किताबों और अनुशासन के माहौल के बीच एक स्कूल में किशोर दोस्ती का विवाद ऐसा उलझा कि मामला सीधे मारपीट तक पहुंच गया। अरौल थाना क्षेत्र के रौगांव स्थित मेवालाल स्मारक स्कूल में एक छात्रा से बातचीत और नजदीकी को लेकर दो छात्रों के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अचानक खुले टकराव में बदल गया। स्कूल परिसर में हुई इस भिड़ंत से कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया।

सूत्रों के मुताबिक, दोनों छात्र एक ही छात्रा से नियमित संपर्क में थे। मोबाइल फोन पर बातचीत और आपसी दावेदारी को लेकर दोनों के बीच पहले भी कहासुनी हो चुकी थी। बताया जाता है कि एक छात्र दूसरे को छात्रा से बात न करने की हिदायत देता था, जिससे आपसी खींचतान बढ़ती गई। इसी तनातनी ने स्कूल समय में ही झगड़े का रूप ले लिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले तीखी बहस हुई, फिर धक्का-मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। मौके पर मौजूद शिक्षकों और अन्य छात्रों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दी।

मकनपुर चौकी स्तर पर शिकायत पहुंचने के बाद पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी जुटाई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि विवाद छात्रा से जुड़े आपसी संबंधों को लेकर था और झगड़े में शामिल छात्रों में एक नाबालिग भी है। इसी बीच घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया, जब स्कूल संचालक ने दूसरी चिट्ठी देकर कार्रवाई न करने का अनुरोध कर दिया। इसके बाद पुलिस ने फिलहाल कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं की। स्थानीय स्तर पर घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। अभिभावकों और ग्रामीणों के बीच स्कूलों में मोबाइल उपयोग, किशोरों की काउंसिलिंग और निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

- छात्रा से दोस्ती और मोबाइल बातचीत बना विवाद की जड़
- "उससे बात मत करो" जैसी चेतावनियों से बढ़ी तकरार
- स्कूल परिसर में ही कहासुनी से मारपीट की नौबत
- एक छात्र और छात्रा एक ही गांव के, दूसरा छात्र सीमा क्षेत्र के गांव का
- स्कूल प्रबंधन ने पहले दी लिखित तहरीर, बाद में लिया यू-टर्न
- झगड़े में एक नाबालिग छात्र शामिल – पुलिस ने बरती सतर्कता
- आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन 'दोनों से बातचीत' की चर्चा तेज
- घटना के बाद स्कूल अनुशासन और मोबाइल मॉनिटरिंग पर बहस तेज

डीएम की छापेमारी के बाद जागी मंडी व्यवस्था, एआरएम ने किया निरीक्षण

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। जिलाधिकारी की अचानक छापेमारी के बाद उत्तरीपुरा मंडी समिति की व्यवस्थाएं हरकत में आती नजर आईं। गुरुवार को एआरएम विजय विक्रम ने मंडी पहुंचकर धान खरीद और तौल व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

एआरएम ने मंडी में रखे धान की जल्द तौल कराने तथा किसानों के खातों में समय से भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान करने या भुगतान में देरी की शिकायत मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

दरअसल, हाल ही में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंडी का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में धान खरीद में सुस्ती और पंजीकरण के बाद भी किसानों को तौल के लिए भटकाने जैसी खामियां सामने आई थीं, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई थी।

कबड्डी में बेटियों का कमाल, बिल्हौर के स्कूल ने जीता स्वर्ण

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। इटावा में आयोजित मंडल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में जूनियर कबड्डी बालिका वर्ग में कंपोजिट विद्यालय गोहलियापुर, बिल्हौर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। फाइनल मुकाबले में टीम ने मेजबान इटावा को 30-2 के बड़े अंतर से पराजित कर एकतरफा जीत दर्ज की।

इस जीत के साथ टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई कर लिया है खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और तालमेल

➪ एकतरफा मुकाबले में इटावा की टीम को दी करारी शिकस्त, अब राज्य स्तर पर दिखाएँगी दमखम

ने पूरे मुकाबले में विपक्षी टीम को संभलने का मौका नहीं दिया। राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका आशा कटियार ने बताया कि पिछले वर्ष यही टीम प्रतियोगिता स्थल पर मामूली देरी से पहुंचने के कारण खेलने से वंचित रह गई थी। उस समय खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपने प्रदर्शन से जवाब दिया।

टीम की सफलता का श्रेय कोच इंशु आर्या को दिया जा रहा है, जो बालिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। उनकी मेहनत और मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि टीम ने मंडल स्तर पर परचम लहराया।खंड शिक्षा अधिकारी रवि कुमार सिंह ने टीम को बधाई देते हुए इसे क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। प्रतियोगिता के दौरान शिक्षक अवनीश कटियार, उषा पाल, आकाश बाजपेई, सलीम, तेज बहादुर और मांडवी सिंह ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

8 वर्षीय बच्ची की मौत पर प्रकाश नर्सिंग होम सील

स्वराज इंडिया फालोअप

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। चौबेपुर क्षेत्र में इलाज के दौरान आठ वर्षीय बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रकाश नर्सिंग होम को सील कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर गलत इलाज और लापरवाही का आरोप लगाया है।भट्ठा कोठी गांव निवासी जितेंद्र कुमार की बेटी शिवानी को 16 फरवरी की शाम तबीयत खराब होने पर नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक 17 फरवरी को हालत बिगड़ने पर उसे दोबारा अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने रामा अस्पताल रेफर कर दिया। रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया।मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने नर्सिंग होम के बाहर शव रखकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत कराया।

पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गलत इंजेक्शन और इलाज में लापरवाही के कारण उनकी बेटी की जान गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर एडिशनल सीएमओ ने नर्सिंग होम को सील कर दिया। संबंधित मेडिकल स्टोर पर भी कार्रवाई की गई है। चौबेपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि तेरे पिता की तहजीब के आधार पर नर्सिंग होम के संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

मौत के बाद ही जागता है स्वास्थ्य विभाग

चौबेपुर में आठ वर्षीय बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली एक बार फिर कटघरे में है। तहसील क्षेत्र के ककवन, चौबेपुर, शिवराजपुर और बिल्हौर ब्लॉक में दर्जनों झोलाछाप डॉक्टर बेखौफ क्लीनिक चला रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक कोई बड़ी घटना सामने नहीं आती, तब तक न तो सख्त जांच होती है और न ही स्थायी कार्रवाई।

इंस्टाग्राम दोस्ती कर महिला का शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती का फायदा उठाकर एक विवाहित महिला का शोषण करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप है।

जानकारी के अनुसार पीड़िता की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए करीब छ महीने पहले शिवराजपुर निवासी शरद यादव से हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपी ने भरोसा जीतकर महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार दबाव बनाता रहा। आरोप है कि बाद में उसने अपने कुछ साथियों को भी इस कृत्य में शामिल कर लिया। विरोध करने पर महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। मामला तब खुला जब पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर परिजनों को आपबीती बताई और थाने में तहरीर दी। थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि गुरुवार को राढ़ा गांव के पास हाईवे अंडरपास के निकट आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

व्यापारियों से पारदर्शी कारोबार और अधिक टैक्स जमा करने का आह्वान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अनैतिक व्यापार में लिप्त व्यापारियों की भी जांच की जाएगी

फर्रुखाबाद। व्यापारी कल्याण से जुड़े पदाधिकारी और राजेंद्र गुप्ता ने व्यापारियों से एक नंबर का काम करने और सरकार को अधिक से अधिक टैक्स जमा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग को उद्योग स्थापित कर रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, न कि केवल नौकरी मांगने की सोच रखनी चाहिए।

नेहरू रोड स्थित व्यापारी नेता अनुपम रस्तोगी के प्रतिष्ठान पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत और व्यवस्थित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन विरोधी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गलत कार्य करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी, जबकि अच्छा काम करने वालों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उद्योग व्यापार मंडल देशभर के करोड़ों व्यापारियों का बड़ा संगठन है। ऐसे व्यापारियों की भी जांच की जाएगी जो सक्रिय कारोबार नहीं कर रहे या अनैतिक व्यापार में लिप्त हैं। अच्छे आचरण और चरित्र वाले व्यापारियों को संगठन से जोड़ा जाएगा।

राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों के खिलाफ दर्ज कुछ एफआईआर सही तरीके से नहीं लिखी गई हैं। इस संबंध में जिला अध्यक्ष को विवाद निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला अध्यक्ष सदानंद शुक्ला ने भरोसा दिलाया कि जांच के बाद गलत मुकदमे समाप्त कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों से वार्ता के बाद गलत धाराएं हटाने और अनावश्यक दबिश रोकने पर सहमति बनी है।

बैठक में व्यापारियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाने और युवाओं को स्वरोजगार व

उद्योग स्थापना के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया गया।

कार्यक्रम में जिला महामंत्री नरेश पालीवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालू कनौजिया, महिला जिलाध्यक्ष सोनी शुक्ला, राकेश सक्सेना, आनंद प्रकाश गुप्ता, अंकुर श्रीवास्तव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन अनुपम रस्तोगी ने किया। व्यापारियों ने प्रदेश महामंत्री का फूल-मालाओं से स्वागत भी किया।

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस के दोषी को कल सरेंडर करना होगा

» 10 साल की सजा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई; कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। उन्नाव कस्टोडियल डेथ मामले में दोषी जयदीप सिंह सेंगर उर्फ अतुल सिंह को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे कल तक संबंधित जेल प्राधिकरण के समक्ष सरेंडर करें। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले की ताजा स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है।

जयदीप सिंह सेंगर इस मामले में सह-दोषी हैं। इस केस में उनके साथ पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर भी दोषी ठहराए जा चुके हैं। जयदीप सिंह सेंगर की ओर से दाखिल याचिका में 10 साल की सजा को सस्पेंड (स्थगित) करने की मांग की गई है। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरेंडर का निर्देश दिया।सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि जयदीप सिंह सेंगर अदालत के आदेश का पालन करते हुए तय समय सीमा के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेंगे।

अदालत ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट मिलने के बाद सजा स्थगन की मांग पर आगे विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद तय की जाएगी।

रमज़ान के पहले जुमे को जामा मस्जिदों में उमड़े रोजेदार

» पेश इमामों ने अदा कराई पहले रमजान के पहले जुमे की नमाज़

रमज़ान में एक नेकी का मिलता है 70 गुना सवाब :मौलाना कुतुबुद्दीन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रसूलाबाद कानपुर देहात। मुकद्दस माह ए रमज़ान चल रहा है। शुक्रवार को रमजान के दूसरा रोज़ा मुकम्मल होगा। वहीं रमजान के दूसरे रोजे को रमजान के पहला जुमा हुआ। जहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के

लोगों ने ब जमात नमाज़ अदा की।

रसूलाबाद कस्बे की प्रचीन जामा मस्जिद में पेश इमाम हाजी अब्दुल रऊफ खान बकाई ने जुमे की नमाज अदा कराई तो वहीं कुरैशी मोहाल में मौलाना कुतुबुददीन ने जुमे की नमाज अदा कराई। नमाज से पहले बयान करते हुए खलीफा ए बहरुल इरफान मौलाना कुतुबुद्दीन ने रमज़ान की फज़ीलतों को बयां करते हुए कहा कि अल्लाह तआला का इरशाद है, कि रमजान वह मुबारक महीना है। जिसमें कुरआन पाक नाजिल किया गया। जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है और फैसले की रोशन बातों पर मुश्तमिल है तो तुम में से जो कोई ये महीना पाए तो जरूर उसके रोज रखें और जो बीमार हो या सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में रखें। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता।

इस महीनें में हम कसरत से खैरात व सदकात करें और गरीबों, बेवाओं यतीमों का सहारा बने। उनकी हर मुमकिन इमदाद करे। हमे चाहिए कि इस रमजान के मुबारक महीने में रोजे रखकर नमाजे बाजमात अदा करके तरावीह पढ़कर नेक आमाल करके अपने रब को राजी करें। इसी प्रकार पठान मोहाल में मौलाना नायाब खान अजहरी ने तो नेहरू नगर में हाफिज मो. शाहिद कुरैशी ने रमजान के पहले जुमे की नमाज अदा कराई। इसी प्रकार रसूलाबाद क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के कस्बों कहिंजरी, असालतगंज,पहाड़ीपुर,बिरहुन सहित दर्जनों मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज़ अदा की और मुल्क की तरक्की व अमन के लिए दुआएं मांगीं। वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध रहे। पुलिस गश्त पर रही तो मस्जिदों के बाहर भी पुलिस फोर्स तैनात रहा।

पुलिस विभाग: त्योहारों से पहले जनपद में चली तबादला एक्सप्रेस

बड़े पैमाने पर उपनिरीक्षकों व प्रभारी निरीक्षकों की तैनाती में किया फेरबदल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रमजान, होली और ईद उल फितर के मद्देनजर जनपद की पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बड़े स्तर पर उप निरीक्षको व निरीक्षकों के तबादले किए। त्योहारों में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे इसको लेकर उन्होंने यह कदम उठाया।

पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने 15 उप निरीक्षकों व निरीक्षकों को इधर से उधर किया। जिसमें रसूलाबाद कोतवाल रहे सतीश कुमार सिंह को भोगनीपुर का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया जबकि उनके स्थान पर शिवनारायण सिंह को रसूलाबाद कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई। प्रभारी निरीक्षक गजनेर जनार्दन प्रताप सिंह को प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा तो शिव कुमार शर्मा को अपराध शाखा में भेजा गया। प्रभारी निरीक्षक गजनेर धीरेंद्र सिंह को रसूलाबाद थाने का क्राइम इंस्पेक्टर बनाया गया। इसी प्रकार शिवली प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार को शिवली थाने से हटाकर सर्विलांस सेल भेजा गया जबकि शिवली थाने की जिम्मेदारी अमरेंद्र बहादुर सिंह को दी गई। जो इससे पहले प्रभारी निरीक्षक भोगनीपुर थे। दिनेश कुमार गौतम को थानाध्यक्ष रनियां, सूर्य प्रताप सिंह को थानाध्यक्ष गजनेर एवं सौरभ कुमार को थानाध्यक्ष देवराहट बनाया। वहीं डेरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चौकी कांधी का चौकी प्रभारी मलिक चंद्र एवं जैनपुर चौकी का प्रभारी प्रशांत कुमार को बनाया गया। उप निरीक्षक अमित शुक्ला व देवनारायन द्विवेदी को क्राइम ब्रांच में जिम्मेदारी दी गई। जबकि उपनिरीक्षक अभिनेष कुमार को थाना रनियां से हटाकर थाना भोगनीपुर में तैनात किया। स्थानांतरित हुए सभी उपनिरीक्षकों और निरीक्षकों को जनपद की पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने तत्काल प्रभाव से चार्ज लेने का आदेश दिया।

नवीपुर में गूंजे जयकारे, भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ

» कलश यात्रा का जगह-जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात माती। जनपद के नवीपुर ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। गांव की गलियों से निकली कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर भक्ति गीतों पर झूमती नजर आईं। जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।

विधिवत पूजन-अर्चन के साथ कथा का शुभारंभ हुआ। यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा पंडाल तक पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश स्थापना की गई। जगह-जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इस पावन आयोजन के यजमान संजय दुबे एवं उनकी पत्नी अनीता दुबे (आयोजक) रहे। साथ ही श्री सत्यनारायण दुबे एवं उनकी पत्नी सरोज दुबे ने भी विधिवत पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अशोक दुबे, अवधेश दुबे, राधेश दुबे, सर्वेश दुबे, पंकज दुबे, शेखर दुबे (श्यामल दुबे), सत्यम दुबे, आशुतोष दुबे (शिवानी दुबे), आदर्श दुबे (आकांक्षा दुबे), गोपी, राघव एवं विष्णु सहित अनेक गणमान्य एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए बैठने, पेयजल एवं प्रसाद वितरण की उत्तम व्यवस्था की गई है। कथा स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में एकता, सद्भाव और संस्कारों की भावना सुदृढ़ होती है।

फैक्कर ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, अस्पताल में हंगामा

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। पनकी क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में पैर के फैक्कर के ऑपरेशन के बाद महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और गलत ऑपरेशन का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने परिजनों ने 30 लाख रुपये मुआवजे की मांग रखी।

» गलत इलाज का आरोप, परिजनों ने मांगे 30 लाख मुआवजा

» अस्पताल का दावा ऑपरेशन के बाद ब्लड प्रेशर नहीं हुआ कंट्रोल

देर रात तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रही।

जानकारी के अनुसार, कानपुर देहात के मैथा निवासी अतुल शुक्ला अपनी पत्नी नीलम के साथ 15 फरवरी को घर लौट रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक के गुजरने से बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे नीलम गिरकर घायल हो गईं। उनके बाएं पैर में फैक्कर हो गया था। इसके बाद उन्हें पनकी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्लास्टर कर ऑपरेशन की सलाह दी।बुधवार सुबह ऑपरेशन के दौरान महिला को एनेस्थीसिया दिया गया और सर्जरी की गई। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के कुछ देर बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हड्डी के ऑपरेशन के बाद कुछ मामलों में ब्लड प्रेशर अचानक गिरने की समस्या आती है। डॉक्टरों के अनुसार, महिला का ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं हो सका, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।पनकी थाना पुलिस का कहना है कि परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच बातचीत जारी है। तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अब नहीं भटकेंगे यात्री: कानपुर सेंट्रल पर खुला हाईटेक यात्री सुविधा केंद्र

एक ही स्थान पर टिकट, ट्रैवल, व्हीलचेयर और कस्टमर सहायता उपलब्ध

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। यात्रियों को सुरक्षित, सरल और सुव्यवस्थित यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर सुविधाओं का विस्तार तेज कर दिया है। इसी क्रम में उत्तर मध्य रेलवे की पहल पर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आधुनिक हाईटेक यात्री सुविधा केंद्र शुरू कर दिया गया है। यह केंद्र प्लेटफार्म नंबर 1 के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में स्थापित किया गया है।

नए केंद्र के शुरू होने से यात्रियों को अलग-अलग सेवाओं के लिए स्टेशन परिसर में भटकना नहीं पड़ेगा। अधिकांश जरूरी सुविधाएं अब एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे समय की बचत होगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी।

यात्री सुविधा केंद्र को इस तरह विकसित किया गया है कि यहां आने वाले यात्रियों को तत्काल मार्गदर्शन और सहायता मिल सके। केंद्र पर भीड़ प्रबंधन सहायता के साथ आरामदायक बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, पेयजल और भोजन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा टिकट संबंधी जानकारी, टूर एंड ट्रैवल सेवाएं, टूर पैकेज बुकिंग और लगेज सहायता भी यहीं से मिल रही है।

दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को विशेष राहत देते हुए व्हीलचेयर सुविधा भी केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। रेलवे का कहना है कि यह केंद्र यात्रियों के लिए 'वन-स्टॉप हेल्प प्वाइंट' के रूप में काम करेगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यात्री कस्टमर केयर नंबर के जरिए अब कई सेवाओं का लाभ मोबाइल फोन से भी लिया जा सकता है। इससे यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले ही जरूरी जानकारी और सहायता मिल सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस मॉडल के यात्री सुविधा केंद्र अब तक देश के 19 प्रमुख स्टेशनों पर शुरू किए जा चुके हैं और आगे अन्य बड़े स्टेशनों पर भी इन्हें स्थापित करने की योजना है।

एक नजर में...

- कानपुर सेंट्रल पर हाईटेक यात्री सुविधा केंद्र शुरू
- प्लेटफार्म नंबर 1 के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में स्थापना
- टिकट, ट्रैवल, टूर पैकेज और लगेज सहायता एक ही जगह
- बैठने, पेयजल, शौचालय और भोजन की सुविधा उपलब्ध
- दिव्यांग यात्रियों के लिए व्हीलचेयर सेवा
- कस्टमर केयर नंबर से मोबाइल पर भी सहायता
- देश के 19 प्रमुख स्टेशनों पर पहले ही शुरू हो चुकी है पहल

तिगाई में दीक्षित कैफे रेस्टोरेंट की हुई विधिवत शुरूआत

» हवन-पूजन के साथ हुआ शुभारंभ

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात. ब्लाक अकबरपुर क्षेत्र के तिगाई गांव में नए दीक्षित कैफे रैस्टोरेंट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधि-विधान से हवन-पूजन के साथ हुआ। इसके बाद समाज सेविका शिखा दीक्षित ने फीता काटकर रैस्टोरेंट का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में कानपुर नगर से प्रसिद्ध यूट्यूबर तनू उर्फ आशीष अग्निहोत्री एवं समाज सेवक नवीन दीक्षित, अशोक दुबे, रज्जुयन मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, हर्ष सक्सेना, अंकुश गुप्ता, महेश नारायण अग्निहोत्री, उमाशंकर दीक्षित, हरिओम सेठ, अनिल दीक्षित, प्रतीक दीक्षित, नवनीत शुक्ला, शैलेश दीक्षित, आशीष तिवारी, मोहित उर्फ झल्लू यादव, राजेश कुशवाहा, गोल्डी, सोनाली, अनिका शुक्ला, सलोनी, आकांक्षा और शिवम सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने रैस्टोरेंट संचालकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधा शुरू होने से स्थानीय लोगों को बेहतर खान-पान की सुविधा मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

रायबरेली में कुम्हार को 1.25 करोड़ रुपए की देनदारी का नोटिस

मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजरा करने वाले कारीगर को डाक से मिला जीएसटी विभाग का नोटिस

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रायबरेली। जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में कुटीर स्तर पर मिट्टी के बर्तन बनाकर परिवार चलाने वाले एक कुम्हार को वस्तु एवं सेवा कर विभाग की ओर से करीब 1 करोड़ 25 हजार रुपये की कर देनदारी का नोटिस जारी किया गया है। डाक के माध्यम से मिले इस नोटिस के बाद पीड़ित परिवार में हड़कंप की स्थिति है। परिजनों के अनुसार इतनी बड़ी रकम की मांग उनके वास्तविक कामकाज और आय से बिल्कुल मेल नहीं खाती।पीड़ित मो. शहीद परंपरागत कुम्हारी का काम करते हैं और स्थानीय बाजारों व हाटों में मिट्टी के बर्तन बेचकर रोजी-रोटी कमाते हैं। उनका कहना है कि उनका कारोबार छोटे स्तर का है और वे किसी बड़े व्यापारिक लेन-देन या थोक आपूर्ति से जुड़े नहीं हैं। ऐसे में करोड़ के

आसपास कर देनदारी का नोटिस मिलना उनके लिए चौंकाने वाला है।

परिवार के मुताबिक नोटिस मिलने के बाद से घर में तनाव का माहौल है। परिजनों ने आशंका जताई है कि कहीं किसी फर्म के गलत पंजीकरण, पहचान विवरण के दुरुपयोग या तकनीकी त्रुटि के कारण यह नोटिस जारी न हो गया हो। पीड़ित ने संबंधित अधिकारियों से मिलकर पूरे मामले की जांच और नोटिस के आधार की जानकारी लेने की बात कही है।स्थानीय लोगों का कहना है कि मो. शहीद लंबे समय से पारंपरिक कारीगरी से जुड़े हैं और उनका काम पूरी तरह श्रम आधारित है। उनका वार्षिक कारोबार भी सीमित बताया जा रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी कर मांग को लेकर क्षेत्र में चर्चा है और लोग इसे विभागीय त्रुटि की संभावना से जोड़कर देख रहे हैं।

कर विशेषज्ञों के अनुसार कई बार गलत जीएसटी पंजीकरण, पैन या आधार नंबर की गड़बड़ी, या किसी अन्य कारोबारी द्वारा गलत विवरण दर्ज करने से भी नोटिस गलत व्यक्ति तक पहुंच सकता है। ऐसे मामलों में दस्तावेजों के साथ विभाग में आपत्ति दर्ज कराई जाती है और सत्यापन के बाद संशोधन संभव होता है। फिलहाल पीड़ित परिवार विभागीय कार्यालय में जाकर अपना पक्ष रखने और रिकॉर्ड की जांच कराने की तैयारी कर रहा है। मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया मिलना अभी बाकी है।

खबरः एक नजर में

- हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कुम्हार मो. शहीद को नोटिस
- डाक से मिला ?1.25 करोड़ कर देनदारी का नोटिस
- कुटीर स्तर पर मिट्टी के बर्तन बनाकर करते हैं जीविकोपार्जन
- परिवार ने रकम को आय के अनुपात से अत्यधिक बताया
- गलत पंजीकरण या तकनीकी त्रुटि की आशंका
- विभाग से जांच और नोटिस की समीक्षा की मांग
- दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी

रोहतास में तिलक समारोह से लौटे पांच लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी

जहरीली शराब, अंग फेल या किसी विषैले पदार्थ की आशंका , कई एंगल से जांच शुरू

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

पटना। बिहार के रोहतास जिले में तिलक समारोह से लौटे पांच व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल है। एक ही गांव के पांच लोगों की कम समय के भीतर हुई मौत ने प्रशासनिक तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सभी मृतक 14 फरवरी की रात एक तिलक समारोह में शामिल होकर लौटे थे, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ती चली गई।मामला बिक्रमगंज अनुमंडल के मठिया गांव से जुड़ा बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार समारोह से लौटने के बाद मृतकों ने बेचैनी, उल्टी, पेट दर्द और अत्यधिक कमजोरी की शिकायत की। कुछ को स्थानीय स्तर पर इलाज दिलाने की कोशिश की गई, जबकि कुछ की हालत तेजी से बिगड़ती चली गई। देखते ही देखते अलग-अलग समय पर पांचों ने दम तोड़ दिया। लगातार हुई मौतों से गांव में शोक और भय का माहौल बन गया।

स्थानीय लोगों के बीच मौत के कारणों को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कुछ ग्रामीण इसे जहरीली शराब के सेवन से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि अन्य लोग किसी दूषित खाद्य पदार्थ, जहरीले रसायन या अचानक अंग फेल होने जैसी आशंका जता रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लक्षणों के आधार पर संभावित कारणों का आकलन कर रही है।

घटना के बाद परिजनों ने सभी शवों का अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे वैज्ञानिक जांच का अहम आधार समाप्त हो गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम न होने से सटीक कारण पता लगाना कठिन हो गया है। अब जांच टीम समारोह में शामिल अन्य लोगों, भोजन-पानी की व्यवस्था, संभावित पेय पदार्थों और मृतकों के मेडिकल इतिहास की जानकारी जुटा रही है।पटना स्तर पर भी अधिकारियों ने रिपोर्ट तलब की है। पुलिस का कहना है कि कॉल डिटेल, आपसी संपर्क, समारोह के आयोजकों और उपस्थित लोगों से पूछताछ के जरिए घटनाक्रम को जोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अफवाहों से बचते हुए तथ्यात्मक आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और रिपोर्ट के बाद ही मौतों की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी।

डीएम राजेश कुमार पाण्डेय की जनसुनवाई से बढ़ा भरोसा, पीड़ितों को मिल रहा त्वरित न्याय

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

उरई / जालौन। प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल जनसुनवाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। नियमित प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनसुनवाई में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने दूर-दराज से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना।जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भूमि विवाद, राजस्व, पुलिस, पेंशन, आवास तथा अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत कीं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक प्रकरण पर संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेते हुए सभी एसडीएम, तहसीलदारों और विभागाध्यक्षों को वर्चुअल माध्यम से जोड़कर मामलों के त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।लोगों ने जिलाधिकारी के सरल व्यवहार और निष्पक्ष कार्यशैली की सराहना करते हुए इसे जनहित में महत्वपूर्ण पहल बताया है।जिले में प्रभावी जनसुनवाई व्यवस्था से प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।

‘नो-डॉक्टर जोन’ बना अयोध्या पशु चिकित्सालय, पब्लिक हो रही परेशान

ड्यूटी टाइम पर गायब रहते हैं डॉक्टर, शिकायत पर अफसरों का गैर-जिम्मेदाराना रवैया

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या।सरकारी दावों के विपरीत अयोध्या स्थित पशु चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह पटरी से उतरती नजर आ रही हैं। अस्पताल में तैनात पशु चिकित्सक अरुणेंद्र सचान पर ड्यूटी के दौरान नियमित रूप से अनुपस्थित रहने के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिससे पशुपालकों और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अस्पताल परिसर में डॉक्टर की उपस्थिति का समय दीवार पर स्पष्ट रूप से अंकित है, लेकिन हकीकत में इसका पालन नहीं किया जा रहा। गुरुवार को अधिवक्ता वैभव सिंह अपने पालतू कुत्ते के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद नहीं मिले। काफी देर इंतजार के बावजूद कोई जिम्मेदार अधिकारी उपलब्ध नहीं हुआ।स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब अक्सर अस्पताल नहीं आते, इसके बावजूद उनकी उपस्थिति रजिस्टर में हाजिरी पूरी रहती है और वेतन भी नियमित रूप से लिया जा रहा है। इससे विभागीय व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले से परेशान होकर जब अधिवक्ता ने लखनऊ स्थित हेड ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई, तो वहां से उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उल्टा उनसे यह कहा गया कि उन्होंने वहां फोन क्यों किया। इस रवैये से विभागीय अधिकारियों की संवेदनहीनता उजागर होती है।

पशुपालकों का कहना है कि समय पर इलाज न मिलने से कई बार पशुओं की हालत गंभीर हो जाती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अस्पताल की लापरवाही से जनता का भरोसा लगातार टूटता जा रहा है। अब देखना यह है कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।

जिला अस्पताल में मरीज से ‘एक रुपये की ठगी’

इलाज नहीं, बहाने मिले!

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

» डॉक्टर निजी क्लिनिक में मस्त, अफसर मौन

अयोध्या। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई है। इलाज की आस लेकर पहुँचे एक अधिवक्ता को घंटों इंतजार के बाद भी डॉक्टर नसीब नहीं हुआ, उल्टे उन्हें मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न झेलना पड़ा। मामला जिला चिकित्सालय अयोध्या से जुड़ा है, जहाँ कथित रूप से मरीजों से सिर्फ पर्चे के नाम पर वसूली हो रही है, इलाज गायब है।

शहर के राधिका कुंज निवासी कुंवर वैभव सिंह गुरुवार को इलाज के लिए अस्पताल पहुँचे। एक रुपये का पर्चा कटवाया, लेकिन 13 नंबर ओपीडी पर चर्म रोग विशेषज्ञ नदारद मिले। घंटों बैठने के बाद भी न डॉक्टर आए, न कोई जिम्मेदार जवाब मिला। आरोप है कि संबंधित डॉक्टर उस समय अपने निजी क्लिनिक में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे।

पीड़ित का कहना है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत अधीक्षक से की तो वहाँ भी सिर्फ बहानेबाजी हुई। न कोई कार्रवाई, न कोई संतोषजनक जवाब। जब अधिकारी ही आंख मूंद लें, तो कर्मचारी और डॉक्टर जवाबदेह कैसे होंगे?

कुंवर वैभव ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि यह सब जानबूझकर सरकार की छवि खराब करने जैसा है। उन्होंने साफ कहा जब सेवा नहीं, व्यवस्था नहीं, तो पर्चे के नाम पर लिया गया पैसा हर्जाने सहित वापस किया जाए।÷ इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जिला अस्पताल में इलाज से ज्यादा चल रहा है ‘उपेक्षा का कारोबार’। गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सिर्फ लाइन, इंतजार और अपमान मिलता है, जबकि डॉक्टर निजी कमाई में व्यस्त रहते हैं।

सफाईकर्मी से दुष्कर्म, सुपरवाइजर समेत तीन पर मुकदमा दर्ज

नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठ रहे गंभीर सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। नगर निगम की व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कोतवाली क्षेत्र में कार्यरत एक महिला सफाईकर्मी ने अपने सुपरवाइजर समेत तीन लोगों पर दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है।

पीड़िता मूल रूप से बाराबंकी की रहने वाली है और अयोध्या नगर निगम में सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत है। उसका पति भी निगम में ही काम करता है। पीड़िता ने 17 फरवरी को पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। पीड़िता के अनुसार, उसका सुपरवाइजर सलमान लंबे समय से उसकी मजदूरी रोककर बैठा था। कई बार मांगने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। मजदूरी दिलाने के बहाने रेखा उसे सलमान के पास ले गई। इसके बाद सलमान उसे रामकथा पार्क स्थित अपने दोस्त नाजिम के कमरे में ले गया।

आरोप है कि नाजिम ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद सलमान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद सलमान और उसकी पत्नी ने उसे धमकाया, ताकि वह किसी से शिकायत न करे। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने बलात्कार और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक ओम प्रकाश को सौंपी गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है।

अयोध्या में एक किलोवाट सौर ऊर्जा प्रणाली का शुभारंभ

» सोलर सिटी बनने की दिशा में बड़ा कदम

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या अब धार्मिक पहचान के साथ-साथ हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। गुरुवार को कृष्णा सोलर इंडस्ट्री द्वारा एक किलोवाट माइक्रो इन्वर्टर आधारित सौर ऊर्जा प्रणाली का शुभारंभ किया गया। यह संस्था टाटा पावर सोलर की अधिकृत सहयोगी कंपनी है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर गिरीश चंद्र त्रिपाठी रहे। उन्होंने कहा कि अयोध्या को स्वच्छ, हरित और ऊर्जा आत्मनिर्भर नगर के रूप में विकसित करना लक्ष्य है। सौर ऊर्जा से बिजली बिल में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से आम जनता को सौर ऊर्जा अपनाने में सुविधा मिल रही है। कृष्णा सोलर इंडस्ट्री के निदेशक उदय प्रताप सिंह ने बताया कि एक किलोवाट सौर प्रणाली की लागत लगभग 70 हजार रुपये है, जिसमें सरकार द्वारा 45 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह प्रणाली प्रतिदिन लगभग 25 यूनिट बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। टाटा पावर सोलर की ओर से क्षेत्रीय प्रमुख शिव लाल, विपणन प्रमुख हिमांशु राय तथा बिक्री प्रमुख आशुतोष त्रिपाठी उपस्थित रहे।

नकली एसटीएफ अफसर बनकर चार लाख की ठगी

» कोतवाली पुलिस ने दबोचा, सफारी कार और यूपी पुलिस का फर्जी पहचान पत्र बरामद

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। खुद को एसटीएफ अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेने वाला एक शातिर ठग आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कोतवाली पुलिस ने जमीन बैनामे का पैसा वापस दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान सुल्तानपुर निवासी अजय कुमार सिंह (52) के रूप में हुई है। उसे रानोपाली मार्ग स्थित उदासीन आश्रम के पास से दबोचा गया। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक सफारी कार (क्र16 श्र 7618) और यूपी पुलिस का फर्जी पहचान पत्र बरामद हुआ है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 26 से 29 दिसंबर 2025 के बीच खुद को एसटीएफ अधिकारी बताकर फर्जी आईडी कार्ड दिखाया और जमीन बैनामे का पैसा वापस दिलाने का झांसा दिया। इस दौरान अलग-अलग तारीखों में पीड़ितों से कुल चार लाख रुपये ऐंठ लिए।

पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। साक्ष्य मिलने के बाद जालसाज को धर दबोचा गया। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी के खिलाफ थाना तारुन में धोखाधड़ी का एक और मुकदमा पहले से दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है और उसके नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है।

यूपी पंचायत चुनाव: बढ़ती तारीखों से चुनाव शेड्यूल पर बड़ा सवाल

दूसरी बार बढ़ी समयसीमा से सियासी पारा चढ़ा, फाइनल वोटर लिस्ट 15 अप्रैल को

क्यों बढ़ी राजनीतिक बेचैनी

- पंचायत चुनाव ग्रामीण सत्ता संरचना की बुनियाद माने जाते हैं
- यही चुनाव आगे के विधानसभा और लोकसभा समीकरणों की जमीन तैयार करते हैं
- वोटर लिस्ट में बदलाव से स्थानीय जातीय और राजनीतिक गणित प्रभावित होता है
- देरी से उम्मीदवार चयन और बूथ मैनेजमेंट रणनीति पर असर पड़ता है
- विपक्ष देरी को "प्रशासनिक कमजोरी" तो सरकार "तकनीकी शुद्धिकरण" बता रही है

कैसे खिसकती गई वोटर लिस्ट

- पहला चरणः अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख 6 फरवरी तय
- दूसरा चरणः बढ़ाकर 28 मार्च की गई
- तीसरा चरणः फिर संशोधन, नई तारीख 15 अप्रैल घोषित
- नई डेडलाइनः तकनीकी व मैपिंग कार्य 13 अप्रैल तक
- अंतिम सूची के बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा संभावित

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा प्रशासनिक अपडेट सामने आया है। अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख दूसरी बार आगे बढ़ा दी गई है और अब फाइनल वोटर लिस्ट 15 अप्रैल को प्रकाशित होगी। पहले यह सूची 28 मार्च को जारी होनी थी। लगातार तारीख आगे खिसकने से चुनाव कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है और राजनीतिक हलकों में इसे लेकर तीखी चर्चा शुरू हो गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के ताजा आदेश के मुताबिक मतदाता सूची का कंप्यूटरीकरण, राज्य मतदाता संख्या आवंटन और मतदेय स्थलों की मैपिंग का काम अभी पूर्ण नहीं हो सका है। इन प्रक्रियाओं को अब 13 अप्रैल तक पूरा करने की नई समयसीमा तय की गई है। इसके बाद 15 अप्रैल को अंतिम सूची जारी होगी। यह दूसरी बार है जब प्रकाशन की तारीख बढ़ाई गई है।

सबसे अहम तथ्य यह है कि ग्राम पंचायतों का मौजूदा कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में मतदाता सूची प्रकाशन, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, नामांकन, जांच, नाम वापसी और मतदान जैसी पूरी प्रक्रिया सीमित समय में पूरी करनी होगी। यही वजह है कि प्रशासनिक तैयारी और कानूनी समयसीमा के बीच संतुलन बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने साफ कहा है कि समयसीमा बढ़ने का मतलब चुनाव

➪ **कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराना प्रशासन के लिए बड़ी अग्निपरीक्षा**

पंचायत चुनाव की वर्तमान स्थिति

- अंतिम मतदाता सूचीः अब 15 अप्रैल
- पिछली तय तारीखः 28 मार्च
- पहली तय तारीखः 6 फरवरी
- सूची संबंधी कार्य पूरे करने की नई सीमाः 13 अप्रैल
- ग्राम पंचायत कार्यकाल समाप्तिः 26 मई
- देरी की संख्याः दो बार समयसीमा बढ़ी
- प्रमुख कारणः कंप्यूटरीकरण, मैपिंग, SIR, परीक्षाएं, फील्ड स्टाफ पर दबाव

टलना नहीं है। उनके अनुसार सरकार निष्पक्ष और त्रुटिरहित मतदाता सूची के साथ तय समय के भीतर चुनाव कराने के पक्ष में है। वहीं विपक्षी दल इसे संभावित देरी का संकेत बताकर सरकार और आयोग दोनों पर दबाव बना रहे हैं।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR), बूथ सत्यापन और अन्य सरकारी अभियानों के कारण जमीनी अमले पर कार्यभार बढ़ा है। बीएलओ और स्थानीय कर्मचारियों की व्यस्तता भी देरी का प्रमुख

कारण बताई जा रही है। मतदाता सूची जारी होने के बाद ही चुनाव की औपचारिक अधिसूचना, नामांकन और मतदान की तारीखें तय होंगी। 26 मई से पहले नई पंचायतों का गठन संवैधानिक आवश्यकता है, इसलिए आने वाले हफ्तों में आयोग की घोषणाएं राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। यह चुनाव अब सिर्फ स्थानीय निकाय का नहीं, बल्कि ग्रामीण राजनीतिक शक्ति परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है।

मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी 2018 की टिप्पणी पर फिर गरमाई सियासत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

सुल्तानपुर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। वर्ष 2018 के इस प्रकरण को लेकर अदालत में करीब 20 मिनट तक कार्यवाही चली, जिसमें राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च तय की है। पेशी के साथ ही इस मामले ने एक बार फिर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है।

कोर्ट परिसर में राहुल गांधी के पहुंचते ही समर्थकों की भीड़ जुट गई। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत करने की कोशिश की, हालांकि राहुल गांधी ने माला पहनने से विनम्रता से इनकार कर दिया और सीधे अदालत कक्ष में प्रवेश किया। पेशी के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर न्यायाधीश का अभिवादन किया और बिना मीडिया से बातचीत किए बाहर निकल गए।

यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें अमित शाह को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है।

➪ **एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी, अगली सुनवाई 9 मार्च, सुरक्षा के बीच राजनीतिक संदेश भी**

इस बयान के विरोध में भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा सुल्तानपुर में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब वर्षों पुराने इस मामले में सुनवाई आगे बढ़ने से इसे राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था की और कई नेताओं व समर्थकों को मुख्य परिसर के बाहर ही रोक दिया।

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने बताया कि अदालत के निर्देश पर बयान दर्ज कराया गया है और आगे की कार्यवाही सुनवाई की अगली तारीख पर होगी। वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता ने संकेत दिया कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त साक्ष्य भी पेश किए जाएंगे।

पेशी के बाद राहुल गांधी रामचेत मोची के परिवार से मिलने भी रवाना हुए, जिससे उनके दौरे को सामाजिक

और जनसंपर्क संदेश से भी जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, कानूनी कार्यवाही के साथ यह दौरा विपक्ष की जनसंपर्क रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com